<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2273

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन

2273. श्री एस. आर. पार्थिबनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र इकाई श्रेणी के ''इस्पात संयंत्रों'' की अवसंरचना में सुधार हेतु इन्हें बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के सरकारी उपक्रमों के विकास हेतु विदेशी इस्पात दिग्गजों के द्वारा कोई तकनीकी सहायता आरंभ की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों की तुलना में उच्च ग्रेड के इस्पात का उत्पादन कर रही सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को भारी वित्तीय प्रावधान प्रदान किया जाता है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या व्यापार के आपूर्ति पक्ष को बढ़ावा देने, विशेषकर सलेम इस्पात संयंत्र जैसे पीएसयू की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के इस्पात संयंत्रों की अवसंरचना में सुधार/विकास के संबंध में निर्णय संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति और बाजार गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने क्रूड इस्पात क्षमता को 12.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से 21.4 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), राऊरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित अपने पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम (तमिलनाडु) स्थित विशेष इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तारण कार्य शुरू किया है।

(ग): जी नहीं।

(घ): सेल के आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजना के भाग के रूप में सेलम इस्पात संयंत्र में न्यू स्टील मेल्ट शॉप की स्थापना करने और कोल्ड रोलिंग मिल की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2371/- करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

****